UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

AUGUST, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 311

NEWSMAKERS

भारत ने 5 साल पहले 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल किया, जानिए किसानों को हुआ इतना भुगतान

भारत ने 2030 के तय लक्ष्य से 5 साल पहले ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का रिकॉर्ड बना लिया है. 2014 में 1.5% से शुरू हुई इस पहल से 2025 तक 661.1 करोड़ लीटर इथेनॉल पेट्रोल में मिला. इससे 698 लाख टन CO_2 उत्सर्जन में कटौती हुई.

भारत ने समय से हासिल किया इथेनॉल ब्लेडिंग का लक्ष्य

भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है. यह उपलब्धि 2030 के निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले 2025 में ही हासिल हो गई है. इसे लेकर इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सरकार की नीति प्रतिबद्धता की तारीफ की है. ISMA ने कहा कि यह मील का पत्थर न केवल भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि किसानों की आमदनी, पर्यावरण संरक्षण और विदेशी मुद्रा की बचत के नजरिये से भी बेहद महत्वपूर्ण है.

इथेनॉल मिशन की बड़ी उपलब्धियां

- **शुरुआत:** 2014 में सिर्फ 1.5% ब्लेंडिंग से शुरुआत हुई थी
- **वृद्धि:** 2014 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर जून 2025 तक 661.1 करोड़ लीटर इथेनॉल ब्लेंड हुआ
- **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** 698 लाख टन CO_2 उत्सर्जन में कटौती
- **किसानों को भुगतान:** 1.18 लाख करोड़ रुपये
- **डिस्टिलरी उद्योग को भुगतान:** 1.96 लाख करोड़ रुपये
- **विदेशी मुद्रा बचत:** 1.36 लाख करोड़ रुपये की बचत

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ

ISMA ने कहा कि भारत का इथेनॉल उत्पादन गन्ना आधारित है, जिसमें गन्ने के रस, B-हेवी मोलासेस और अन्य उप-उत्पादों से इथेनॉल तैयार किया जाता है. इससे एक ओर जहां चीनी मिलों को आर्थिक मजबूती मिली, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिला है.

ISMA के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा,

"यह उपलब्धि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रामीण समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग है. यह इथेनॉल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक किसान, मिल और हितधारक के लिए अत्यंत गर्व का विषय है. सरकार की अटल नीतिगत दिशा और दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल इस राष्ट्रीय सफलता को निर्धारित समय से पांच साल पहले संभव बनाया है, बल्कि हरित ऊर्जा में हमारे सामूहिक भविष्य के लिए एक शक्तिशाली मिसाल भी स्थापित की है."

पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में कदम

इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश की तेल आयात पर निर्भरता घटी है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ हुआ है. पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से न केवल प्रदूषण घटा है, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है.

भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA), भारत में चीनी और जैव-ऊर्जा उद्योग का सर्वोच्च निकाय है, जो अनुकूल सरकारी नीतियों के माध्यम से निजी चीनी मिलों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित है.

ISMA उद्योग की चिंताओं को दूर करने और विकासोन्मुखी नीतियां बनाने के लिए राज्य चीनी संघों और सरकार के साथ मिलकर काम करता है. यह देश में चीनी और जैव-ऊर्जा उद्योग के विकास और गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है.

Source: Kisan Tak, 25th July, 2025

P.T.O ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

AUGUST, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 311

अगस्त 2025 के लिए 22.5 लाख टन मासिक चीनी कोटा जारी; 25.20 LMT थी अगस्त 2024 में खपत

नई दिल्ली : खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को अगस्त 2025 के लिए 22.5 लाख मीट्रिक टन मासिक चीनी कोटे का ऐलान किया, जो अगस्त 2024 के लिए आवंटित कोटे से कम है। अगस्त 2024 में, सरकार ने घरेलू बिक्री के लिए 22 लाख मीट्रिक टन का मासिक चीनी कोटा आवंटित किया था। जुलाई 2025 के लिए भी चीनी कोटा का आवंटन 22 लाख मीट्रिक टन था।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अधिक माँग के कारण जुलाई में कीमतों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि देखी गई। रक्षा बंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, श्रावण आदि जैसे त्योहारों के कारण अगस्त का कोटा अपेक्षित माँग से कम प्रतीत होता है; इसलिए, बाजार में कीमतों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि होने की संभावना है। पिछले साल अगस्त में चीनी की खपत 25.20 लाख मीट्रिक टन थी।

Source: Chinimandi, 28th July, 2025

बाढ़ से पांच हजार हेक्टेयर गन्ने की फसल प्रभावित

अमरोहा : जिलें में बाढ़ के चलते तक़रीबन पांच हजार हेक्टेयर गन्ना फसल प्रभावित हुई है। इससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर में कहा गया है की, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर डीसीओ ने गंगा नदी के समीपवर्ती गन्ना विकास परिषद/चीनी मिल चंदनपुर एवं गजरौला क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। विभागीय एवं चीनी मिल अधिकारियों की टीमों का गठन कर गांवों का नाव के जरिए भ्रमण किया।

डीसीओ ने कहा कि, वर्तमान में लगभग पांच हजार हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। अधिकतर क्षेत्रों में चार से पांच फीट तक पानी भरा है।जिन गन्ना खेतों में जलभराव कम है, उनकी चीनी मिल की सहायता से समय से बंधाई कराने की सलाह दी गई है। किसानों को बताया कि गन्ना विकास विभाग ने बाढ़ ग्रस्त गन्ना किसानों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर 7078577200 जारी किया है। एससीडीआई, सचिव व मिल अधिकारी एवं कर्मचारी भी सहायता में लगे हैं।

Source: Chinimandi, 08th August 2025

केंद्र ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा डिनेचर्ड एथेनॉल पर हाल ही में किए गए नीतिगत बदलावों का संज्ञान लिया : मंत्री सुरेश गोपी

नई दिल्ली : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को राज्यसभा को सूचित किया की, केंद्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा डिनेचर्ड एथेनॉल (Denatured Ethanol) पर हाल ही में किए गए नीतिगत बदलावों, विशेष रूप से नवीनीकरण शुल्क, लाइसेंस शुल्क, भंडारण शुल्क, क्षमता वृद्धि शुल्क, आयात/निर्यात शुल्क आदि जैसे शुल्कों के संबंध में का संज्ञान लिया है। तदनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाया है और राष्ट्रीय एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और इस तथ्य के मद्देनजर कि एथेनॉल वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत आता है, ऐसे शुल्कों/शुल्कों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश राज्य डिनेचर्ड एल्कोहल पर 1 रुपये प्रति बोतल निर्यात शुल्क लगाता है।

मंत्री सुरेश गोपी ने कहा, केंद्र सरकार ने इन राज्य सरकारों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड) से आग्रह किया है कि वे तर्कसंगत उत्पाद शुल्क/शुल्क और सहायक नियामक ढाँचे के माध्यम से राज्यों के भीतर और बाहर एथेनॉल उत्पादन, भंडारण और परिवहन को सुगम बनाएँ। राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखित करने, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, उन्होंने कहा "जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, प्रयासों में तालमेल बिठाने के लिए जैव ईंधन के संबंध में मंत्रालयों/विभागों/राज्यों सहित सभी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है।

उन्होंने कहा, यह जैव ईंधन कार्यक्रमों के समग्र समन्वय, प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के सहयोग से ASSET (सतत राज्य ऊर्जा संक्रमण में तेजी) प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है ताकि राज्य स्तर पर उभरती प्रौद्योगिकियों, चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और क्षेत्रीय डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण ब्लूप्रिंट और कार्यान्वयन रोडमैप का सह-निर्माण किया जा सके।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 (जिसे 2022 में संशोधित किया गया था) ने अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 से बढ़ाकर एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 कर दिया है। सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) पेट्रोल में

Continued on the next page ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

AUGUST, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 311

एथेनॉल मिलाकर बेचती हैं। चालू ESY 2024-25 के दौरान, OMCs ने 31.07.2025 तक 19.05% का औसत एथेनॉल मिश्रण प्राप्त कर लिया है। जुलाई 2025 में, 19.93% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त कर लिया गया है।

एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एथेनॉल उत्पादन हेतु फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:

- 2022 में संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अनुसार एथेनॉल उत्पादन हेतु फीडस्टॉक का विस्तार।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) द्वारा एथेनॉल प्लांट्स के आसपास मक्का क्लस्टर का विकास और आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) द्वारा अनाज आधारित डिस्टलरीयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मक्का उत्पादन बढ़ाने हेतु "एथेनॉल उद्योगों के जलग्रहण क्षेत्रों में मक्का उत्पादन में वृद्धि" शीर्षक से एक परियोजना।
- सरकार द्वारा एथेनॉल उत्पादन हेतु भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अधिशेष चावल के 52 लाख मीट्रिक टन (LMT) आवंटन को मंजूरी दी गई है। यह आवंटन -ESY 2024-25 (1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक) और ESY 2025-26 (30 जून 2026 तक) के लिए होगा।
- ESY 2024-25 के लिए एथेनॉल उत्पादन हेतु 40 लाख मीट्रिक टन चीनी के उपयोग की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, देश में एथेनॉल उत्पादन के साथ-साथ आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल खरीद के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र की शुरुआत की, ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया, मोलासेस के साथ-साथ अनाज से एथेनॉल उत्पादन के लिए 2018-22 के दौरान विभिन्न एथेनॉल ब्याज सबवेंशन योजनाएं (ईआईएसएस) शुरू कीं, मौजूदा गन्ना आधारित डिस्टलरीयों को एथेनॉल उत्पादन के लिए बहु-फीडस्टॉक प्लांट में बदलने के लिए सहकारी चीनी मिलों के लिए एक समर्पित सबवेंशन योजना सरकार द्वारा 06 मार्च, 2025 को अधिसूचित की गई है।

Source: Chinimandi, 12th August, 2025

SUGAR INDUSTRY URGES GOVERNMENT TO EXTEND EXPORT PERMISSION TILL 31ST DECEMBER

The Government permitted sugar exports of 1 million tonnes during the current 2024-25 sugar season. However, with the season ending in two months, the industry is concerned that the total export quota may not be met.

According to the sugar apex body ISMA, by mid-July 2025, India had exported between 650,000 and 700,000 tonnes of sugar. The association hopes to export a total of 800,000 tonnes by the end of September, leaving around 200,000 tonnes unexported.

International sugar prices are strong due to increased demand, encouraging exporters to sell the remaining stock to generate revenue. Rahil Shaikh, MD of MEIR Commodities, suggested that the Government should extend the export permissions for the current season until 31st December 2025, enabling the remaining 200,000 tonnes to be exported.

He explained, "The reason that this 200,000 tonnes of sugar hasn't been exported is that it's either lying in Uttar Pradesh or in locations where it can't be exported during this season due to logistical constraints, like large volumes and weather-related issues".

The Managing Director of NFCSF, Prakash Naiknavare said that the decision to allow 1 MT of sugar export was excellently timed. "It helped improve cash liquidity of mills, which in turn helped make cane payments to the farmers. Therefore, giving extension till December 2025 will help complete the quota without giving any adverse impact on domestic sugar prices," he added.

India is forecast to have a bumper sugar harvest in 2025-26. The USDA projects sugar production to reach 35 million tonnes (raw value) in the upcoming season, increase from this year.

Shaikh added that with expectations of a good cane crop next year, allowing an export of about 1 to 1.5 million tonnes, there is no reason why the remaining 200,000 tonnes should not be exported, as it would benefit the country.

"India should not be seen as an unreliable player in the international market. We should be recognised as a consistent and committed sugar producing and exporting nation," he concluded.

Source: Chinimandi, 21st July, 2025

'SUGAR PRODN DIPS 23% IN 7 YES DESPITE RISE IN CANE ACREAGE'

Lucknow: UP's sugarcane sector has witnessed an intriguing trend with sugar production by mills falling by almost 23% between 2017 - 18 and 2024 – 25, despite a substantial increase in cane acreage and productivity during the period.

Sources attribute the dip to diversion of cane for khandsari, low

Continued on the next page ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

AUGUST, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 311

recovery and advese weather condition.

Data released by the cane development shows that the area undercane cultivation increased by almost 28% - from 22.99 lakh hectares in 2024-25. Likewise, the productivity also increased from 79.19 tonnes per hectare to 83 tonnes per hectare signifying a rise of around 5%.

Even cane production went up from 1820.75 lakh tones (L/T) to 2456.35 LT during the same period. The number of mills crushing cane also rose from 119 to 1222, one of the highest in recent times. However, the sugar production dropped from 120.5 lakh tones in 2017-18 to 92.45 lakh tones in 2024-25, a fall of around 23%. In 2023-24, sugar production in the state was pegged at around 104.13 lakh tones. The cane crushing season in UP ended in june earlier this year.

Yet, UP happens to be the biggest production of sugar in the country, surpassing Maharashtra. The western state was the leading producer of sugar last year when it produced around 110 lakh metric tonnes of sugar. This, however, plunged below 90 LMT in 2024-25 Nationally, the total sugar production is estimated to be around 330 lakh tonnes.

The fall in sugar production is largely attributed to the diversion of sugar from cane mills to khandsari, a traditional, unrefined Indian sugar made from sugarcane juice. It's a natural sweetener that retains more nutrients and molasses than refined whitesugar. According 250 Khandari units for quicker compensation compared to the one paid by the mills. the shift gained pertinence against the backdrop of the state govt. keeping the SAP for sugar at Rs 370 per quintal (for early variety) and Rs 360 per quintal for general variety. Another key reason behind the downturn in sugar production is adverse weather condition – drought and excess rainfall – besides a drop in the quality of cane.

Source: TOI, 06th Aug, 2025

Knowledge Box

Brazil is Turning Sugarcane Waste into Stronger and Greener Asphalt.

Brazil is quietly spearheading a revolution in sustainable infrastructure by turning sugarcane waste into roads. In an innovative twist, Brazilian researchers have discovered that sugarcane bagasse ash, the ashy residue left after sugarcane is processed for sugar and ethanol, can replace a key ingredient in asphalt. The result is a pavement that they claim is is stronger, longer-lasting, and dramatically more eco-friendly.

UPSMA Newsletter titled 'Varta' the Dialogue is providing information on sugar, sugar industry and sugar byproducts. We request you to share your thoughts and experience with us through write-ups, success stories, updates, photographs etc. We publish your creative in the next edition of this newsletter. You are requested to send your entries to be published in UPSMA newsletter through mail at upsma@upsma.org. The newsletter will be uploaded on UPSMA website.

अस्वीकरण: यहाँ दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा या अन्य स्रोतों से ली गई है, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है और इस पर इस तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस समाचार में दी गई जानकारी में किसी भी अनजाने त्रुटि से किसी भी व्यक्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए 'वार्ता टीम' किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी इस समाचार की तारीख तक है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य के परिणाम या घटनाएँ इस जानकारी के अनुरूप होंगी।

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org